National Seminar on Inclusive Growth in Rural India conducted at ICFAI University – March 18, 2021

Morning India
www.sanmarglive.com
11 Ranchi, Friday
19 March 2021

National Seminar on Inclusive Growth in Rural India conducted at ICFAI University

A two-days National Seminar on 'Inclusive Growth in Rural India through Self-Help Groups (SHG) & Farmer Producer Organizations (FPO)' was conducted through an live-video conference at ICFAI University. The Guests of Honor included Smt. Radhika Rastogi, Deputy Director General, National Institute of Rural Development & Panchayati Raj (NIRDPR), Hyderabad, Sri Paritosh Upadhyay, Chief Conservator of Forests (CCF), Government of Jharkhand, Sri Ashish Kumar Padhi, Chief General Manager(CGM), NABARD, Jharkhand, and Dr. Ramesh Mittal, Director, National Institute of Agricultural Marketing(NIAM), Jaipur.

Welcoming the participants at the Inaugural Session, Prof D R S Rao, Vice Chancellor of the University said, "Resilience of Agriculture to Indian Economy was demonstrated during the recent COVID-19, wherein Agricultural Production went up though rest of the economy suffered." "In the last few years, Government of India has promoted developmental institutes like SHGs and FPOs to enhance the income of the farmers. However, there are a number of challenges in implementation. The objective of the conference is to discuss the issues and arrive at solutions for the same", added Prof Rao.

In her message to the participants, Smt. Draupadi Murmu, Honorable Governor of Jharkhand said "The very idea of Atma Nirbhar Bharat will become a reality by co-operation of Government Organizations and NGOs as SHGs in co-operative mode".

Addressing the seminar, Smt Radhika Rastogi highlighted the role of MEDM and SHG formation in India. "Today, Villages are subsidizing the cost of living in urban areas. The SHGs are actively participating in various income generating activities through Poultry, Dairy and other Agricultural allied areas. Because of this, the cost of intermediation has reduced and these sectors are going through a transformation. Women SHGs are being managed very efficiently and are able to attract large volume of credit from the banks, as their net NPA is less than 2 percent", she explained.

Smt Rastogi also shared success stories of SHGs and FPOs from several states of India, to illustrate her points.

Recalling the historical developments of FPOs in India, Sri Ashish Kumar Padhi explained the contribution of NABARD in setting up and capacity building of FPOs in India and in particular, the State of Jharkhand. "358 FPOs were set up by NABARD in Jharkhand so far, with most of them reaching the stage of viability and 32 more will be set up shortly", added Sri Padhi.

Sri Paritosh Upadhyay exhorted the need for Social Mobilization and Capacity Building for the development of SHGs. While describing the status of SHGs in the State of Jharkhand, he expressed that financial literacy and financial discipline are the key to the success of SHG movement in the state. He also suggested that a cluster level approach so that more facilities are benefitted in the state.

Dr. Ramesh Mittal highlighted that value addition by way of better Agri Business Management should be the thrust area for both SHGs and FPOs. "Jharkhand can be uniquely positioned to leverage its favourable climatic conditions and rich forest cover, by focusing on Minor Forest products, Medicinal and Aromatic plants", Dr. Mittal added. Prof Arvind Kumar, Registrar and Dr. Bhagabat Barik, Asst. Dean and the Seminar Coordinator also spoke on the occasion.

सन्मार्ग
रांची, शुक्रवार, 19 मार्च 2021
www.live7tv.com

इक्फाई में ग्रामीण भारत में समावेशी विकास पर राष्ट्रीय संगोष्ठी

संवाददाता

रांची : इक्फाई विश्वविद्यालय, झारखंड में ऑनलाइन वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) और किसान उत्पादक संगठनों के माध्यम से ग्रामीण भारत में समावेशी विकास पर दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। उद्घाटन सत्र में प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए, विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो ओआरएस राव ने कहा, भारतीय अर्थव्यवस्था में कोविड-19 के दौरान कृषि के प्रति लचीलापन हाल ही में प्रदर्शित किया गया, जिसमें कृषि उत्पादन बाकी अर्थव्यवस्था के मुकाबले ऊपर चला गया था। पिछले कुछ वर्षों में भारत सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए एसएचजी और एफपीओ जैसी विकास संबंधी पहलों को बढ़ावा दिया है। इसके कार्यान्वयन में कई चुनौतियां हैं। प्रो राव ने कहा कि सम्मेलन का उद्देश्य इसी मुद्दों पर चर्चा करना और उसके समाधान पर पहुंचना है। राष्ट्रीय संगोष्ठी में राज्यपाल द्रोपदी मुर्मू ने प्रतिभागियों को अपने संदेश में कहा, आत्मनिर्भर भारत का विचार सरकारी संगठनों और गैर-सरकारी संगठनों के सहयोग से एक सहकारी समिति के रूप में स्वयं सहायता समूह बन जायेगा। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास व पंचायती राज संस्थान के उप महानिदेशक राधिका रस्तोगी ने भारत में एनडीएम और एसएचजी गठन की भूमिका पर प्रकाश डाला। आज, ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में रहने की लागत पर सब्सिडी दे रहे हैं। एसएचजी में पोल्ट्री, डेयरी और अन्य कृषि संबद्ध क्षेत्रों के माध्यम से विभिन्न आय सृजन गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। इस वजह से, मध्यस्थता की लागत कम हो गई है और ये क्षेत्र परिवर्तन से गुजर रहे हैं। मुख्य वन संरक्षक आशीष कुमार ने बताया कि नाबार्ड का योगदान भारत में और विशेष रूप से झारखंड राज्य में एफपीओ की स्थापना और क्षमता का निर्माण किया गया है।

राष्ट्रीय सागर
रांची
शुक्रवार, 19 मार्च 2021
12
web: rashtriyasagarprime.com

इकफाई विवि में ग्रामीण भारत में समावेशी विकास पर राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित

राष्ट्रीय सागर संवाददाता

रांची : इकफाई विश्वविद्यालय, झारखंड में ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) और किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के माध्यम से ग्रामीण भारत में समावेशी विकास पर दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस राष्ट्रीय संगोष्ठी में सम्मानित अतिथियों में श्रीमती राधिका रस्तोगी, उप महानिदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर), हैदराबाद, परितोष उपाध्याय, मुख्य वन संरक्षक (सीसीएफ), झारखंड सरकार, आशीष कुमार पाढ़ी, मुख्य महाप्रबंधक (सीजीएम), नाबार्ड, झारखंड सरकार और डॉ. रमेश मित्तल, निदेशक,

राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान (एनआईएएम), जयपुर से शामिल थे। राष्ट्रीय संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र में प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए, विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो ओआरएस राव ने कहा, भारतीय अर्थव्यवस्था में कोविड-19 के दौरान कृषि के प्रति लचीलापन हाल ही में प्रदर्शित किया गया, जिसमें कृषि उत्पादन बाकी अर्थव्यवस्था के मुकाबले ऊपर चला गया था। पिछले

कुछ वर्षों में, भारत सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए एसएचजी और एफपीओ जैसे विकास संबंधी पहलों को बढ़ावा दिया है। हालांकि, इसकी कार्यान्वयन में कई चुनौतियां हैं। प्रो राव ने कहा की सम्मेलन का उद्देश्य इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करना और उसी के समाधान पर पहुंचना है। राष्ट्रीय संगोष्ठी में झारखंड की माननीय राज्यपाल श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने प्रतिभागियों को दिए अपने संदेश में कहा, आत्मनिर्भर भारत का विचार सरकारी संगठनों और गैर-सरकारी संगठनों के सहयोग से एक सहकारी समिति के रूप में स्वयं सहायता समूह बन जाएगा। संगोष्ठी को संबोधित करते हुए श्रीमती राधिका रस्तोगी ने भारत में एनडीएम और एसएचजी गठन की भूमिका पर प्रकाश डाला। आज, ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में रहने की लागत पर सब्सिडी दे रहे हैं। एसएचजी में पोल्ट्री, डेयरी और अन्य कृषि संबद्ध क्षेत्रों के माध्यम से विभिन्न आय सृजन गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। इस वजह से, माध्यस्थता की लागत कम हो गई है और ये क्षेत्र परिवर्तन से गुजर रहे हैं। उन्होंने समझाया की महिला एसएचजी को बहुत कुशलता से प्रबंधित किया जा रहा है और बैंकों से बड़ी मात्रा में ऋण लिया जा रहा है, क्योंकि उनका शुद्ध एनपीए 2 प्रतिशत से कम है। रस्तोगी ने भारत के कई राज्यों से एसएचजी और एफपीओ की सफलता की कहानियां भी साझा कीं। राष्ट्रीय संगोष्ठी में भारत में एफपीओ के ऐतिहासिक विकास को याद करते हुए, आशीष कुमार पाढ़ी ने बताया कि नाबार्ड का योगदान भारत में और विशेष रूप से झारखंड राज्य में एफपीओ की स्थापना और क्षमता का निर्माण किया गया है। श्री आशीष कुमार पाढ़ी ने कहा की अब तक झारखंड में नाबार्ड द्वारा 158 एफपीओ स्थापित किए गए थे, जिनमें से अधिकांश व्यवहार्यता के चरण तक पहुंच गए थे और जल्द ही 32 और स्थापित किए जाएंगे। परितोष उपाध्याय ने एसएचजी के विकास के लिए सामाजिक गतिशीलता और क्षमता निर्माण की आवश्यकता पर जोर दिया।

---

04 खबर मन्त्र
रांची, शुक्रवार
19.03.2021
रांची-सिटी

सरकारी और गैर सरकारी संगठनों में सहयोग जरूरी

इकफाई विवि में ग्रामीण भारत में समावेशी विकास पर राष्ट्रीय संगोष्ठी

खबर मन्त्र ब्यूरो

रांची। इकफाई विश्वविद्यालय झारखंड ने ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) और किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के माध्यम से ग्रामीण भारत में समावेशी विकास पर दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय संगोष्ठी में राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने प्रतिभागियों को दिये अपने संदेश में कहा कि आत्मनिर्भर भारत का विचार सरकारी संगठनों और गैर-सरकारी संगठनों के सहयोग से एक सहकारी समिति के रूप में स्वयं सहायता समूह बन जाएगा। वहीं, विवि के कुलपति प्रो ओआरएस राव ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कोविड-19 के दौरान कृषि के प्रति लचीलापन हाल ही में प्रदर्शित किया गया। इसमें कृषि उत्पादन बाकी अर्थव्यवस्था के मुकाबले ऊपर चला गया था। पिछले कुछ वर्षों में, भारत सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए एसएचजी और एफपीओ जैसी विकास संबंधी पहलों को बढ़ावा दिया है। हालांकि, इसकी कार्यान्वयन में कई चुनौतियां हैं। प्रो राव ने कहा की सम्मेलन का उद्देश्य इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करना और उसी के समाधान पर पहुंचना है। संगोष्ठी में सम्मानित अतिथियों में उप महानिदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण

विकास और पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर) हैदराबाद की राधिका रस्तोगी, सीसीएफ परितोष उपाध्याय, नाबार्ड के सीजीएम आशीष कुमार पाढ़ी और निआम जयपुर के निदेशक डॉ रमेश मित्तल शामिल थे।

संगोष्ठी में राधिका रस्तोगी ने भारत में एनडीएम और एसएचजी गठन की भूमिका पर प्रकाश डाला। कहा कि आज, ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में रहने की लागत पर सब्सिडी दे रहे हैं। एसएचजी में पोल्ट्री, डेयरी और अन्य कृषि संबद्ध क्षेत्रों के माध्यम से विभिन्न आय सृजन गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। इस वजह से, मध्यस्थता की लागत कम हो गई है और ये क्षेत्र परिवर्तन से गुजर रहे हैं। उन्होंने समझाया की महिला एसएचजी को बहुत कुशलता से प्रबंधित किया जा रहा है और बैंकों से बड़ी मात्रा में ऋण लिया जा रहा है, क्योंकि उनका शुद्ध एनपीए 2 प्रतिशत से कम है। श्रीमती रस्तोगी ने भारत के कई राज्यों से एसएचजी और एफपीओ की सफलता की कहानियां भी साझा कीं। राष्ट्रीय संगोष्ठी में भारत में एफपीओ के ऐतिहासिक विकास को याद करते हुए आशीष कुमार पाढ़ी ने बताया कि नाबार्ड का योगदान भारत में और विशेष रूप से झारखंड राज्य में एफपीओ की स्थापना और क्षमता का निर्माण किया गया है। वहीं, परितोष उपाध्याय ने एसएचजी के विकास के लिए सामाजिक गतिशीलता और क्षमता निर्माण की आवश्यकता पर जोर दिया। झारखंड राज्य में एसएचजी की स्थिति का वर्णन करते हुए, उन्होंने कहा कि वित्तीय साक्षरता और वित्तीय अनुशासन राज्य में एसएचजी आंदोलन की सफलता की कुंजी है। डॉ रमेश मित्तल ने कहा कि केवल एग्री बिजनेस मैनेजमेंट के माध्यम से वैल्यू एडिशन एसएचजी और एफपीओ दोनों के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र होना चाहिए। मौके पर रजिस्ट्रार प्रो अरविंद कुमार और असिस्टेंट डीन डॉ भगत बारिया ने भी अपने विचार रखे।

आज
रांची, १९ मार्च २०२१

इक्फाई विवि में दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन

रांची। इकफाई विश्वविद्यालय, झारखंड में ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) और किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के माध्यम से ग्रामीण भारत में समावेशी विकास पर दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस राष्ट्रीय संगोष्ठी में सम्मानित अतिथियों में राधिका रस्तोगी, उप महा. निदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर), हैदराबाद, परितोष उपाध्याय, मुख्य वन संरक्षक (सीसीएफ) , झारखंड सरकार, आशीष कुमार पाढ़ी, मुख्य महाप्रबंधक (सीजीएम), नाबार्ड, झारखंड सरकार और डा. रमेश मित्तल, निदेशक, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान (एनआईएएम), जयपुर से शामिल थे। राष्ट्रीय संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र को विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो ओआरएस राव ने संबोधित किया और कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कोविद-19 के दौरान कृषि के प्रति लचीलापन हाल ही में प्रदर्शित किया गया, जिसमें कृषि उत्पादन बाकी अर्थव्यवस्था के मुकाबले ऊपर चला गया था।